

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राप्तिकारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकारण में दक्षिणात

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1976/पौष 27, 1897

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1976/PAUSA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग सकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th January 1976

S.O. 44(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 34(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Containers and Closures Limited, remain suspended upto the 18th January, 1974, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th of January, 1974;

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto the 18th of January, 1976.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 18th January, 1977;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 18th January, 1977.

[No. F. 2(17)/72-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(शैक्षणिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

का० आ० 44 (अ)/18 एफ बी/प्राइडी प्रार ए/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व शैक्षणिक विकास मंत्रालय (शैक्षणिक विकास विभाग) के आदेश स० का० आ० 34(अ)/18 चब/उ०वि०वि०आ०/73 तारीख 19 जनवरी, 1973 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर, करार, परिनिधारण, पंचाट स्थायी आदेश या अन्य लिखित (उनसे भिन्न जो यैकां या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं), जिनका मैमर्स कन्टेनर्स एप्ट क्लोजर्स लिमिटेड नामक शैक्षणिक उपकरण एक पक्षकार है या जो उक्त शैक्षणिक उपकरण को लागू हों, का प्रवृत्तन 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोटोकूल या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता और दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1976 तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार वा समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः श्रब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चब की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश का अधिधि 18 जनवरी, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 2(17)/72 सी० म० सी]

दी० के० सवसेना, संयुक्त सचिव।